न्यायमूर्ति हरबंस लाल के समक्ष

शेर सिंह - याचिकाकर्ता
बनाम

विजय कुमार और अन्य, -प्रतिवादी

1979 का सिविल संशोधन क्रमांक 124

12 अक्टूबर 1979

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5)

आदेश 20 नियम 14 - प्री-एम्प्शन डिक्री के लिए मुकदमा - प्री-एम्प्शनर द्वारा अंतिम तिथि पर चेक द्वारा डिक्रीटल राशि जमा करना - चेक द्वारा ऐसी जमा राशि - क्या आदेश 22 नियम का पर्याप्त अनुपालन है 14. माना जाता है कि इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि व्यापार और वाणिज्य के विकास की वर्तमान स्थिति में इन दिनों में भुगतान स्वीकृत और अच्छी तरह से स्थापित भुगतान पद्धति में है।

किसी भी व्यक्ति से यह अपेक्षा करना अवास्तविक है कि वह अदालत या राजकोष में जमा करने के लिए अपनी जेब में चांदी के सिक्कों या करेंसी नोटों में राशि ले जाएगा, भले ही वह राशि लाखों में हो। सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा कोर्स और भी खतरनाक हो सकता है. चेक का केवल यह अर्थ और संकेत है कि चेक जारी करने वाले के पास बैंक में उसके खाते की वही राशि है जिसे अदाकर्ता के खाते में जमा किया जा सकता है और चेक प्रस्तुत करने पर, भुगतान करने के लिए चेक जारीकर्ता वह सब कुछ करता है जो उसके लिए आवश्यक है।नकद भुगतान या चेक के माध्यम से भुगतान बराबर है। हालाँकि, यदि चेक जारी करने वाले के खाते में चेक की राशि नहीं है या किसी अन्य कारण से चेक बाउंस हो जाता है, तो परिणाम समान नहीं होगा। उस स्थिति में चेक की प्रस्तुति को भुगतान नहीं माना जा सकता। हालाँकि, ऐसी स्थिति को छोड़कर, चेक के माध्यम से डिक्रीटल राशि का भुगतान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 नियम 14 का पर्याप्त अनुपालन होगा।

(पैरा 15)

धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका श्री आर. डी. अनेजा, एच.सी.एस. के न्यायालय के आदेश के पुनरीक्षण के लिए उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, गुड़गांव ने 8 जनवरी 1979 को विचाराधीन डिक्री की

निष्पादन कार्यवाही के खिलाफ आपत्तियों पर फैसला सुनाया, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं था।

दावा: समझौता डिक्री दिनांक 27 सितंबर 1976 की निष्पादन कार्यवाही में धारा 47 सी.पी.सी. के तहत निर्णय देनदार की आपत्ति याचिका

पुनरीक्षण में दावा:-निचली अदालत के विवादित आदेश को रद्द करने के लिए।

याचिकाकर्ता के वकील जी सी गर्ग।

प्रतिवादियों की ओर से के.सी.पुरी और सी.बी.गोयल, अधिवक्ता।

निर्णय

न्यायमूर्ति हरबंस लाल,

(1) निर्धारण हेतु विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न है; क्या प्री-एम्प्शन डिक्री के निष्पादन में डिक्रीटल राशि का भुगतान, निर्णय-देनदार द्वारा चेक के माध्यम से, आदेश XIX नियम 14, सिविल प्रक्रिया संहिता (इसके बाद इसे संहिता कहा जाएगा) के तहत एक वैध निविदा है?

(2) तथ्य विवादित नहीं हैं। ज्वाला देवी नाम की एक महिला ने अपनी जमीन कैप्टन विजय कुमार, प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में बेच दी।उत्तरार्द्ध ने कब्जे और निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया (इसके बाद इसे पहला मुकदमा कहा जाएगा) जिसका फैसला 27 सितंबर, 1976 को एक समझौते के आधार पर किया गया था। इस बिक्री के संबंध में, पूर्व-खालीगी के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था। शेर सिंह, याचिकाकर्ता, कैप्टन विजय कुमार के खिलाफ, प्रतिवादी-प्रतिवादी। याचिकाकर्ता के पक्ष में प्री-एम्प्शन सूट का फैसला सुनाया गया था और उसे 15 मई, 1978 को या उससे पहले कोर्ट में डिक्रीटल राशि की शेष राशि 11,202 रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था। पहले मुकदमे का फैसला एक समझौते के आधार पर किया गया था। इस आशय से कि यदि प्री-एम्प्शन सूट डिक्री किया गया था और प्री-एम्प्शन टोर डिक्री-धारक ने कानून के अनुसार डिक्रीटल राशि जमा की थी, तो

प्रतिवादी कैप्टन विजय कुमार का मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। अन्यथा उसका वाद डिक्री हो चुका माना जायेगा।

(3) प्री-एम्प्शन डिक्री के निष्पादन में। याचिकाकर्ता शेर सिंह ने 15 मई, 1978 को निष्पादन न्यायालय में शेष डिक्रीटल राशि के रूप में 11,202 रुपये जमा करने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिस पर निष्पादन न्यायालय ने चालान जारी किया। डिक्री धारक ने उक्त राशि को नकद में राजकोष में जमा करने के बजाय, उसी दिन चालान के साथ इस राशि का चेक जमा कर दिया। हालाँकि, चेक की राशि अगले दिन, यानी 16 मई, 1978 को सरकार को जमा कर दी गई।

(4) कैप्टन विजय कुमार, प्रतिवादी नंबर 1, ने इन परिस्थितियों में 27 सितंबर 1976 को पारित डिक्री को एक समझौते के आधार पर निष्पादित करने के लिए एक निष्पादन आवेदन दायर किया, इस आधार पर कि डिक्री धारक प्री-एम्प्शन सूट, डिक्री की शर्तों के अनुसार एक वैध निविदा बनाने में विफल रहा था और इसलिए, उक्त सूट को खारिज कर दिया गया माना जाएगा, और वह विवाद में भूमि पर कब्जा करने का हकदार था। इन निष्पादन कार्यवाही में, प्री-एम्प्शन डिक्री-धारक, याचिकाकर्ता ने आपत्ति उठाई कि उसने 15 मई, 1978 को चेक के माध्यम से डिक्री राशि का वैध टेंडर किया था और इस प्रकार डिक्री कानूनी रूप से पारित हो गई थी। और वैध रूप से निष्पादित किया गया। ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्ति को खारिज कर दिया और माना कि प्री-एम्प्शन डिक्री के निष्पादन में चेक के माध्यम से डिक्री राशि की निविदा वैध नहीं थी और परिणामस्वरूप, मुकदमा खारिज कर दिया गया।

(5) प्री-एम्प्शन सूट में डिक्री संहिता के आदेश XX नियम 14 में निहित निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए, जिसका प्रासंगिक भाग नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"14. प्री-एम्प्शन मुकदमे में डिक्री।-

(1) जहां न्यायालय किसी विशेष बिक्री के संबंध में प्री-एम्प्शन के दावे का फैसला करता है ,संपत्ति और क्रय-धन का भुगतान न्यायालय में नहीं किया गया है, डिक्री होगी-

(ए) एक दिन निर्दिष्ट करें जिस दिन या उससे पहले खरीद-पैसा का भुगतान किया जाएगा; और

(बी) निर्देश देगा कि खंड (ए) में निर्दिष्ट दिन पर या उससे पहले, वादी के खिलाफ डिक्री की गई लागत (यदि कोई हो) के साथ ऐसी खरीद राशि का अदालत में भुगतान करने पर, प्रतिवादी संपत्ति पर कब्जा कर लेगा। वादी को, जिसका हक ऐसे भुगतान की तारीख से अर्जित माना जाएगा, लेकिन, यदि

खरीद-पैसा और लागत (यदि कोई हो) का भुगतान नहीं किया जाता है, तो मुकदमा लागत के साथ खारिज कर दिया जाएगा।

(2) (ए) ... (बी) ...

वर्तमान मामले में भी, यह विशेष रूप से प्रदान किया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा 15 मई, 1978 को या उससे पहले देय राशि का भुगतान किया जाना था। विवाद का मूल यह है कि उक्त प्रावधान में दिशा का आयात क्या है कि खरीद-पैसा, यदि डीरी के पारित होने के समय पहले से ही अदालत में भुगतान नहीं किया गया है तो भुगतान किया जाएगा। इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में इस प्रावधान की व्याख्या की गई है, जिसका संदर्भ निष्पादन न्यायालय के फैसले में किया गया है और मेरे समक्ष बहस के दौरान दोनों पक्षों के विद्वान वकील द्वारा भी उद्धृत किया गया है। उन सभी निर्णयों का बारीकी से अध्ययन करने पर कोई संदेह नहीं रह जाता है कि इस प्रावधान की कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए। (6) शियो राम बनाम झाबर और अन्य[1] में, कपूर, जे द्वारा यह माना गया था कि केवल यह तथ्य कि पूर्व-खाली मुकदमे में निर्णय-लेनदार के पास आवेदन करने के समय धन था - इसे राजकोष में जमा करने के लिए प्रावधान का पर्याप्त अनुपालन नहीं किया गया था और निविदा केवल तभी पूरी की जा सकती थी जब पैसा वास्तव में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो।

(7) काली चरण बनाम रवि दत्त और अन्य[2]में, टेक चंद, जे. ने यह भी माना कि केवल भुगतान करने की पेशकश एक वैध निविदा नहीं है और निविदाकर्ता को न केवल पैसे का भुगतान करने के लिए तैयार होना चाहिए, बल्कि अदालत में डिक्रीटल राशि भी पेश करते हैं और वास्तव में पेश करते हैं।

(8) देस राज बनाम देस राज और अन्य[3] में, डिक्री धारक ने डिक्री में निर्दिष्ट अंतिम दिन प्री एम्प्शन सूट में डिक्रीटल राशि जमा करने के लिए एक आवेदन किया। इस पर कोर्ट ने कार्यालय से अगले दिन रकम जमा होने की रिपोर्ट तलब की। पंडित, जे. द्वारा यह माना गया कि न्यायालय के उठने से ठीक पहले अंतिम तिथि पर धन जमा करने के लिए आवेदन करने मात्र को डिक्री के अनुपालन के रूप में व्याख्या नहीं किया जा सकता है।

(9) शाम सिंह बनाम पाल सिंह[4] में। डिक्री धारक अंतिम तिथि पर उसे जमा करने के लिए डिक्री राशि के साथ निष्पादन न्यायालय में गया चूंकि पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर थे, इसलिए उन्होंने ट्रेजरी अधिकारी से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने आवेदन पर न्यायालय के आदेश के बिना एमो स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद डिक्रीकर्ता अपने आवेदन पर अपेक्षित आदेश प्राप्त करने के लिए

---

[1] एएलआर. 1951 पी.बी. 209.
[2] 1957 पी.एल.आर. 204.
[3] 1968 करंट लॉ जर्नल
[4] ए.आई.आर. 1955 पंजाब 140.

तहसीलदार के पास गया, जिसे न्यायालय की शक्तियां सौंपी गई थीं। आदेश मिलने के बाद जब डिक्री धारक राशि जमा करने के लिए कोषागार में गया तो वह पहले ही बंद हो चुकी थी। ट्रेजरी अधिकारी से संपर्क करने से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उस समय निविदा स्वीकार नहीं की गई थी। इन विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कपूर, जे. द्वारा इसे कानून के आदेश का पर्याप्त अनुपालन माना गया क्योंकि डिक्री-धारक सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, छुट्टी पर पीठासीन अधिकारी के रूप में निविदा नहीं दे सका।

(10) प्रीतम सिंह एवं अन्य बनाम संत सिंह एवं अन्य[5]में। डिक्री-धारक ने अंतिम तिथि के एक दिन बाद बैंक में राशि जमा कर दी क्योंकि अंतिम दिन बैंक बंद था। गुरदेव सिंह, जे. द्वारा यह कहा गया कि डिक्री-धारक को इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि बैंक अंतिम दिन बंद रहेगा और यह ऐसा मामला नहीं है जहां अचानक छुट्टी घोषित की गई हो। डिक्री-धारक का यह कर्तव्य था कि वह न्यायालय में धन प्रस्तुत करे या इस अवधि की समाप्ति से पहले निर्णय-देनदार के लिए और यह माना गया कि डिक्री-होल्ड द्वारा धन का केवल कब्ज़ा पर्याप्त नहीं था जब तक कि इसे विधिवत प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(11) दलावर सिंह और अन्य बनाम सावन सिंह[6] में, अंतिम दिन न्यायालय में डिक्री धारक द्वारा डिक्री राशि का आदेश न्यायालय के आदेश के तहत एक वैध अनुपालन माना गया था, वास्तव में पैसा अगले दिन राजकोष में जमा कर दिया गया।

(12) इस बात पर विवाद नहीं किया गया है कि यदि आवेदन पर सीओ का आदेश प्राप्त करने के बाद डिक्री धारक द्वारा डिक्री धारक द्वारा डिक्री में निर्दिष्ट अंतिम दिन पर डिक्री राशि जमा कर दी जाती है, तो वही होगा कंपनी के आदेश XX के नियम 14 में निहित निर्देश का पूर्ण और वैध अनुपालन होना चाहिए और यह आवश्यक नहीं है कि भुगतान न्यायालय में ही किया जाना चाहिए। आम तौर पर और आम तौर पर, राशि न्यायालय के कार्यालय में प्राप्त नहीं होती है; जमा की जाने वाली राशि प्राप्त करने के लिए न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत चालान जारी करने के लिए कोषागार को केवल निर्देश जारी किया जाता है। किसी मामले में, राजकोष न्यायालय के एजेंट के रूप में कार्य करता है और आदेश के अनुपालन में जमा प्राप्त करने के लिए न्यायालय के प्रतिनिधि के रूप में कर्तव्य करता है। वर्तमान मामले में, डिक्री धारक याचिकाकर्ता द्वारा डिक्री राशि जमा करने के लिए डिक्री में निर्दिष्ट अंतिम दिन पर आवेदन किया गया था। कोर्ट ने उसी दिन आदेश पारित किया और चालान भी जारी कर दिया | यह वह दिन था जब डिक्री-धारक ने डिक्री राशि के बराबर चेक देकर राजकोष में जमा राशि स्वीकार कर ली थी। यह भी विवादित नहीं है कि चेक राजकोष द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन प्रतिवादी का मामला यह है कि चेक की राशि उस दिन नहीं, बल्कि अगले

---

[5] 1971 पी.एल.जे. 361
[6] 1973 पी.एल.जे. 348

दिन उचित शीर्षक के तहत जमा की गई थी और इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि निविदा डिक्री में दिए गए निर्देश के अनुसार राशि का भुगतान नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार। करेंसी नोटों या सिक्कों के साथ-साथ चेक के माध्यम से भुगतान एक ही है और चेक निर्दिष्ट अंतिम दिन पर प्रस्तुत किया गया था, यह वैध निविदा थी। किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त[7]और मोहिदून बी और अन्य बनाम खातून बी और अन्य[8] पर जोर दिया गया है।

13) किर्लोस्कर ब्रदर्स के मामले (सुप्रा) में, कर की राशि का भुगतान चेक द्वारा किया गया था जिसे कुछ समय दिया गया था, लेकिन बाद में भुना लिया गया था। इसे डिवीजन बेंच ने इस प्रकार माना: "चेक के तहत भुगतान चेक की तारीख से संबंधित होता है। इसलिए जब चेक भुनाया जाता है तो यह मायने नहीं रखता है, महत्वपूर्ण यह है कि चेक कब दिया गया था, और भुगतान तब किया जाता है जब चेक दिया गया था न कि चेक कब दिया गया था लेनदार के कहने पर भुनाया गया था। नतीजतन, जब किसी लेनदार द्वारा एक चेक को सशर्त भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है, तब भी लेनदार द्वारा नकद के बजाय चेक स्वीकार करने की प्राथमिकता चेक देने पर लेनदार को भुगतान के रूप में काम करती है। दिया गया है, हालांकि चेक के अंततः भुनाए नहीं जाने की स्थिति में देनदार की देनदारी पुनर्जीवित हो सकती है।"

(14) महिदीन बी के मामले (सुप्रा) में भी, यही दृष्टिकोण अपनाया गया और यह माना गया कि चेक जारी करना नकद में भुगतान के समान ही था। विद्वान वकील ने सेंट्रल ट्रेजरी रूल्स, वॉल्यूम 1 के नियम 80 पर भी भरोसा किया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि चेक द्वारा भुगतान के मामले में, भुगतान चेक के दिन किया गया माना जाएगा। पेश की जाती हैं। इस प्रस्ताव के विपरीत, ठाकुर दास और अन्य बनाम तुलसी दास[9] में पूर्ण पीठ के फैसले के आधार पर एक विपरीत दृष्टिकोण पेश किया गया है, जिसमें प्री-एम्प्शन के लिए एक डिक्री के निष्पादन में, डिक्री धारक ने दो वचन जमा किए थे। भारत सरकार के नोट, एक वर्ष 1854-55 का और दूसरा वर्ष 1865 का, दोनों 500 रुपये के। और दोनों पर 4 प्रतिशत ब्याज है। तथ्यों के आधार पर, न्यायालय द्वारा यह निम्नानुसार देखा गया: "यह स्वीकार नहीं किया गया है या पाया गया है कि इस जमा के समय 1,000 रुपये पर देय ब्याज के साथ या उसके बिना उनका कुल मूल्य क्या था, यह स्वीकार किया गया है कि वादी द्वारा प्रतिवादी को उनका समर्थन नहीं किया गया था।" यह माना गया कि डिक्री-धारक ने अदालत में दो वचन पत्र देकर अदालत को डिक्री राशि का भुगतान नहीं किया। यह भी आयोजित किया गया,- "पहले प्रश्न के संबंध में हमारी राय है कि इसका उत्तर सकारात्मक में दिया जाना चाहिए। कोर्ट में 2 प्रॉमिसरी नोट्स ने खरीद धन की राशि का भुगतान नहीं किया, अर्थात, रु1,000 न्यायालयों में, भले ही यह मान लिया जाए कि उनका मूल्य रुपये था 1,000। अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि उन्होंने रुपये में

---

[7] आकाशवाणी. 1952 बम्बई 306
[8] ए.आई.आर. 1966 मद्रास 435
[9] 70 पंजाब रिकार्ड 1890

परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को जमा करके उस राशि के बराबर राशि प्रदान की। 1,000. यदि कोई वादी पैसे का भुगतान करने के बजाय समतुल्य राशि जमा कर सकता है, तो ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि वह समतुल्य अन्य रूप न ले, जैसे कि गहने, या अनाज या अन्य प्रतिभूतियाँ, जैसे कि प्रॉमिसरी नोट या बांड या निजी व्यक्तियों के बंधक कार्य . हम मानते हैं कि धारा की शर्तों के अनुसार यह आवश्यक है कि जमा धनराशि होनी चाहिए, और वादी धन जमा करने में विफल रहा है।"

(15) मेरी सुविचारित राय में, वचन पत्र और चेक को एक ही आधार पर नहीं माना जा सकता है। सरकारी वचन पत्र के मूल्य में उतार-चढ़ाव जारी है, जो निश्चित रूप से चेक की राशि के मामले में नहीं है। इसके अलावा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यापार और वाणिज्य के विकास की वर्तमान स्थिति में चेक द्वारा भुगतान आजकल भुगतान का एक स्वीकृत और अच्छी तरह से स्थापित तरीका है। किसी भी व्यक्ति से यह अपेक्षा करना बहुत अधिक और अवास्तविक है कि वह अदालत या राजकोष में जमा करने के लिए अपनी जेब में चांदी के सिक्कों या करेंसी नोटों में राशि ले जाएगा, भले ही वह राशि लाखों में हो। सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा कोर्स और भी खतरनाक हो सकता है. चेक का अर्थ केवल यह है कि चेक जारी करने वाले के पास बैंक में उसके खाते में वही राशि है, जिसे अदाकर्ता के खाते में जमा किया जा सकता है और चेक प्रस्तुत करने पर, भुगतान करने के लिए चेक जारीकर्ता वह सब कुछ करता है जो उसके लिए आवश्यक है।

मेरे विचार में, नकद भुगतान या चेक के माध्यम से भुगतान बराबर है। हालाँकि, यदि चेक जारी करने वाले के खाते में चेक की राशि नहीं है या किसी अन्य कारण से चेक बाउंस हो जाता है, तो परिणाम समान नहीं होगा। उस स्थिति में, चेक की प्रस्तुति को भुगतान नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, ऐसी स्थिति को छोड़कर, चेक के माध्यम से डिक्रीटल राशि का भुगतान कानून के प्रावधान का पर्याप्त अनुपालन होगा।

(16) प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन के साथ न्यायालय में चेक प्रस्तुत नहीं किया गया था, बल्कि इसे केवल बैंक को प्रस्तुत किया गया था? इस तथ्य पर दूसरी ओर कोई विवाद नहीं है । हालाँकि, वही सारहीन है। भले ही राशि बैंक में नकद में जमा की गई हो, लेकिन उसे वास्तव में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया होगा। जमा की निविदा, नकद में, या चेक के माध्यम से और बैंक या कोषागार द्वारा इसकी स्वीकृति, जैसा कि मामला यह हो सकता है, कि इसे न्यायालय के समक्ष जमा और स्वीकृति माना जाए, क्योंकि बैंक या कोषागार कार्य करता है और न्यायालय के आदेश का अनुपालन करता है जैसा कि पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत जारी चालान में व्यक्त किया गया है।

(17) ऊपर उल्लिखित कारणों से, यह माना जाता है कि डिक्रीटल राशि की जमा राशि याचिकाकर्ता द्वारा वैध और कानूनी रूप से जमा की गई थी। नतीजतन, प्रतिवादी द्वारा दायर निष्पादन आवेदन

को खारिज कर दिया जाना चाहिए। परिणाम यह हुआ कि पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया गया और विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया। इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चाहत

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अंबाला, हरियाणा